526

- (vii) Inspections and enquaries are conducted on a regular basis of various intermediaries in securities market.
- (b) and (c) No such suggestion has been made by the Company Law Board to SEBI.

Reserved Constituencies

734 SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether on descheduling of a chunk of Scheduled Caste population with adoption of Buddhism by them, the number of reserved Assembly constituencies Parliamentary and were proportionately reduced 1960s in different States, particularly in Maharashtra:
- (b) if so, whether these Buddhists have again veen recognised as Scheduled Castes belonging to respective castes during 1990s, thus considerably increasing the number of Scheduled Castes population; and
- (c) whether in view of this conin Scheduled siderable increase Castes Population with inclusion of Scheduled neo-Buddhists amongst Caste. Government have taken steps to increase the number of Reserved constituencies under article 330 and 952 of the Constitution of India; if so, the steps taken in this regard?

STATE IN THE MINISTER OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE (SHRI AND COMPANY AFFAIRS H R BHARDWAJ): (a) and Neo-Buddhist were treated as belong. ing to Scheduled Castes in 1990 as (Scheduled per the Constitution Castes) Orders (Amendment) Act, 1990.

(c) In terms of the proviso under Article 330 of the Constitution, no change in the existing ratio of representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is called for until the relevant figures in the first census taken after the year 2000 have been published.

Reported unearthing of Rs. 42 crores scandal

735 SHRI SUSHILKUMAR SAM-BHAJIRAO SHINDE:

SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER pleased to state:

- (a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem captioned, "Rs. 42 crore scandal unearthed" which appeared ĺn Hindustan Times of 22nd December, 1994; and
- (b) if so, what are the details of the findings of the investigations made in regard to this scandal indicating the modus operandi of involved scandal and the persons therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS H. R. BHARDWAJ): (a) Yes Sir.

(b) Criminal cases have been registered by Central Bureau of vestigation. Special Crime Branch. Calcutta against Shri Pawan Kumar Ruia and others for alleged complicity in floating a large number limited companies through unscrupulous means with a view to facilitating laundering of black money into white. The CBI is still making investigation in the matter.

Mahila Courts in the Country

BISI: SHRI SANATAN 736. Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) how many Mahila Courts are functioning in the country; and
- (b) the total number of cases instituted and disposed of during the year ending 1994?

THE MINISTER OF STATE THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ: (a) As available information. Courts have been established in the N.C.T. of Delhi with effect from 31st August, 1994, No Mahila Court has been set up in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Kenala, Meghalaya, Manipur, Mizoram. Madhya Pradesh, Tripura. Tamil Nadu, Sikkim and Jammu and Kash-

(b) The number of cases instituted disposed of in the Women Courts of Delhi during the year 1994 is given below:

Instituted—31 Recd by transfer— 1879 Disposed of —234

Information in respect of remaining States Union Territories is still awaited and will be laid on the Table of the House.

न अभाग में द्वारा मामजों का शीख निषटान

737. श्री आज मोहशम्मदः क्या ष्रवात मंत्रो यह बताने जी क्रुपा करेंगे कि:

- (क) क्या विभिन्न न्यायालयों में लिम्बन मामलों को शीझ निषटाने के लिए कोई नित्रम अथवा कातून नहीं बनाये गये हैं;
- (ख) थदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; ग्रीर
- (ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए 1989 में सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति (न्यायमूर्ति मलिमथ समिति) का गठन किया गया था। समिति ने विभिन्न पहलुओं पर कई सिफा-रिशों की थीं जो अधिकारिता और प्रक्रिया

संबंधी उपांतरणों, न्यायपालिका में सुधार, विनिदिष्ट प्रकार के मामलों से निपटने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त निकायों जैसे कि प्रधिकरणों/आयोगों का गठन, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या नियत करना ग्रीर न्यायाधीशों की नियुक्तियां,

करना म्रार न्यायाधाशा का नियाक्तया,
म्रधीनस्थ न्यायपालिका में म्रधिक पदों
का सृजन म्रौर न्यायालयों में कार्याजय
उपस्करों के म्राधुनिकीकरण से संबंधित
म्रोनेक म्रन्य साधारण सिफारिशें तथा
न्यायपालिका को मौर म्रधिक निधियों का
माबंदन, म्रादि, के संबंध में हैं। इन

प्रावश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्याया-लयों को भेज दिया नया था। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या से यथासंभव शीझता

से निपटने के तरीकों ग्रौर उपायों का पता

लगाने के संबंध में मुख्य मंत्रियों और उच्च

सिफारिशों की, अन्य बातों के माथ-साथ

न्यायालयों के मुख्य त्यायमूर्तियों की 4 दिसम्बर, 1993 को हुई बैठक में विचार किया गया था जिसकी ग्रध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी। सम्मेलन ने उसके द्वारा ग्रंगीकृत संकल्प में न्यायालयों/ग्रधिकरणों

विभिन्न उपायों की सिफारिश की थीं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है ग्रीर ग्रावश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ग्रीर उच्च न्यायालायों/ग्रिधिकरणों को भेज

दिया है। तत्पश्चात्, ग्रामीण मुकदमेबाजी

में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए

प्रशासनिक प्रधिकरणों में बकाया मामलो भौर विवादों के भ्रानुकल्पिक समाधान की बाबत उपरोक्त संकल्प में भ्रंतिविष्ट सिफा रिशों पर विचार करने के लिए विधि मंत्रियों के तीन कर्ष्य समझों की बैठन

मंत्रियों के तीन कार्य समूहों की बैठव हुई। विधि मंत्रियों ने कलकत्ता में नवम्ब